छत्तीसगढ़

सहकारी समाचार

वर्ष- 22 अंक - 05 जून 2025 प्रथम अंक (पाक्षिक) RNI NO. CHHHIN/2012/45105 पृष्ठ-12 मूल्य 500/- वार्षिक

पीएम मोदी के नेतृत्व में सहकारिता को घर-घर तक पहुंचाने की संकल्पना हो रही है पूरी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री अपेक्स बैंक के नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी के पदभार ग्रहण में हुए शामिल

मुख्यमंत्री ने अपेक्स बैंक की नई शाखा फरसाबहार का किया वर्चुअल शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी श्री केदारनाथ गुप्ता के पदभार ग्रहण व अभिनंदन समारोह एवं राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में शामिल हुए और उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले के फरसाबहार में अपेक्स बैंक की नई शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किया और क्षेत्रवासियों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार किया जा रहा है। उनकी प्रेरणा से प्रदेश के घर-घर को सहकारिता से जोडने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। श्री साय ने कहा कि नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी के नेतृत्व में प्रदेश में सहकारिता को और अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि सहकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल ही में हमने दुधारू पशु वितरण का शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश के 6 जिलों का चयन कर हितग्राहियों को दो-दो दुधारू गाय वितरित की जा रही हैं।

1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र खोले गए : सीएम

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश के किसानों और ग्रामीण जनों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की एक बड़ी पहल हमने इस वर्ष पंचायती राज दिवस से प्रारंभ की है। प्रदेश के 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र खोले गए हैं, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत भवन में ही बैंकिंग सुविधा मिल रही है। उन्होंने बताया कि अगले पंचायती राज दिवस तक यह सुविधा प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध हो जाएगी, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

सहकारिता के क्षेत्र में हो रहे चमत्कारिक परिवर्तन : डा. रमन

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में सहकारिता का बीजारोपण करने वाले महान विभूतियों को पुण्य स्मरण करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि, छत्तीसगढ़ में श्री वामनराव लाखे और ठाकुर प्यारेलाल जैसे पुरोधाओं ने सहकारिता की नींव रखी, जिसका विकसित स्वरूप आज हम सभी देख रहे हैं। यह वर्ष सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, और केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के प्रयासों से निश्चित रूप से इस क्षेत्र में चमत्कारिक परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के अथक प्रयासों से प्रदेश के किसानों के जीवन में खुशहाली आई है। पूरे देश में वे पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रति एकड़ 21 क्विंटल और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय ने सहकारिता को राज्य के अंतिम गांव तक पहुंचाने का कार्य किया है। अपेक्स बैंक प्रदेश में 40 हजार करोड़ रुपए के टर्नओवर के साथ सबसे शक्तिशाली संगठन है और इसके माध्यम से अब तक 7 हजार 5 सौ करोड़ रुपए का ऋण किसानों को उपलब्ध कराया गया है।

सहकारिता को आगे बढ़ाने का काम करेंगे : गुप्ता

अपेक्स बैंक के नवनियुक्त प्राधिकृत अधिकारी केदारनाथ गुप्ता ने अपने सम्बोधन में प्रदेश सरकार व भाजपा नेतृत्व को विश्वास दिलाया कि, वह और विभागीय मंत्री व अपेक्स बैंक की टीम अब हर महीने अपने काम का रोडमैप बनाएंगे, उसकी समीक्षा करेंगे और हर साल एक-एक पायदान सहकारिता को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। श्री गुप्ता ने अपने प्रति व्यक्त विश्वास और सौंपे गए दायित्व के लिए मुख्यमंत्री श्री साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन महामंत्री पवन साय समेत सभी भाजपा पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जब-जब भाजपा की सरकार आती है, तब-तब एक सकारात्मक बदलाव नजर आता है। प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्ति, सेवा और सुशासन का भाव लेकर भाजपा की सरकार काम करती है।

इन अतिथियों की भी रही मौजूदगी

पदभार ग्रहण समारोह में सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, विधायक श्री राजेश मूणत, विधायक श्री अनुज शर्मा, विधायक श्री मोतीलाल साहू, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, विधायक गुरु खुशवंत साहेब, विधायक श्री सुनील सोनी, विभिन्न निगम-मंडलों के अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव सहकारिता श्री सुब्रत साहू और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

किसानों की समृद्धि की दिशा में काम कर रही सरकार : केदार कश्यप

प्रदेश के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री साय किसानों की समृद्धि के चिंतन पर हमेशा बल देते हैं। अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में डॉ. रमन सिंह ने किसानों को भरपूर सम्मान दिया, उनकी समृद्धि की चिंता की, आज मुख्यमंत्री श्री साय उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार की धान खरीद नीति की चर्चा करते हुए श्री कश्यप ने कहा कि प्रदेश के 2,739 उपार्जन केंद्रों के जरिए प्रदेश में 149 लाख मीटरिक टन धान खरीदा गया है। प्रदेश सरकार इसके अलावा दुग्ध, मत्स्य, लघु वनोपज समितियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और अभी प्रदेश में 711 इन समितियों को गठन हुआ है तथा 530 नई अपेक्स समितियाँ और गठित की जा रही हैं। श्री कश्यप ने कहा कि किसानों के सहयोग और सहकार से समृद्धि तक पहुँचना है क्योंकि बिना सहकार, नहीं उद्धार।

सीएम साय की मौजूदगी में मना 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' और सुशासन तिहार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 29 मई को रायपुर जिले के आरंग विधानसभा के ग्राम भैंसा में विकसित कृषि संकल्प अभियान और सुशासन तिहार के संवाद से समाधान शिविर में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 10 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में किसान बंधु उपस्थित रहे।

इस आयोजन में इफ्को ने स्टाल लगा कर हिस्सा लिया। स्टाल के माध्यम से इफ्को किसानों को इफ्को के उत्पाद, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, बायो-फर्टीलाइजर, विशिष्ट उर्वरकों के बारे में जानकारी दी गई। इससे जुड़े उपयोग और तरीकों के लिए लिफ्लेट भी दिये गये। डीएपी उर्वरक की किल्लत के समय में अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का उपयोग करने की सलाह भी किसानों को दी गई। इफ्को के स्टाल में नमो ड्रोन दीदी श्रीमती चंद्रकली वर्मा ग्राम चंद्रखुरी, जिला रायपुर

से एवं ड्रोन पायलेट श्री पंकज साहू ग्राम रोहांसी जिला बलौदा बाज़ार से भी अपने ड्रोन के साथ स्टाल में उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने किया स्टाल का निरीक्षण : मुख्यमंत्री के स्टाल विजिट के दौरान नैनो डीएपी से बीजोपचार, थरहा उपचार, रोपा-उपचार का तरीका एवं नैनो डीएपी नैनो यूरिया से छिड़काव के फायदों के बारे में जानकारी दी गई। नमो ड्रोन दीदी से मिलकर मुख्यमंत्री ने उनकी कार्यशैली के बारे में चर्चा की। कार्यक्रम में श्री राम विचार नेताम मंत्री कृषि विकास एवं किसान कल्याण, रायपुर के कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह व कृषि विभाग से भी कई अधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में इफ्को से उप-महाप्रबंक रायपुर, राजेश गोले, क्षेत्र प्रतिनिधि मुस्कान तिवारी, एस.एफए. देवी दयाल यादव स्टाल में उपस्थित रहे एवं किसानों को जानदारी दी।

भटपल्ली में जल जीवन मिशन से साकार हुआ हर-घर जल का सपना

रायपुर। जल जीवन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भोपालपटनम विकासखण्ड स्थित ग्राम पंचायत तिमेड़ के आश्रित ग्राम भटपल्ली ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र में अनुकरणीय उपलब्धि हासिल की है। यह ग्राम अब राज्य के उन चुनिंदा गांवों में शामिल हो गया है जहां हर घर में नल से शुद्ध पेयजल की सतत आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। पूर्व में ग्राम भटपल्ली में जल आपूर्ति की एकमात्र व्यवस्था हैंडपंपों पर निर्भर थी, जिससे ग्रामीणों को पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। गर्मी के महीनों में हैंडपंपों के जवाब देने की स्थिति में जल संकट और भी गंभीर हो जाता था। लेकिन अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से ग्राम के 81 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

कोलचूर सेवा सहकारी समिति के सदस्यों को दिया गया प्रशिक्षण

बस्तर। छत्तीसगढ राज्य सहकारी संघ के तत्वावधान में आदिवासी सदस्य सहकारी शिक्षा योजना अंतर्गत बस्तर संभाग के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कोलचूर के सदस्यों ने सहकारी प्रशिक्षण प्राप्त किया।

सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी विवेकानंद झा द्वारा किसानों को सहकारिता का अर्थ, महत्व, सिद्धांत, सहकारी ऋणनीति, समिति के उद्देश्य, सदस्यों के अधिकार, कर्तव्य, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अधिकार, कर्तव्य, बैठक का महत्व, आमसभा, संस्था में रखे जाने वाले रिकॉर्ड, सहकारिता से समृद्धि कैसे लाया जाए सहकारी बैंक का महत्व के बारे में जानकारी प्रदान किया गया। 31 मई को लेंपस प्रबंधक श्री गौतम तिवारी द्वारा किसानों को सीएससी सुविधा के बारे में तथा खाद वितरण एवं बीमा के बारे में जानकारी दिया गया। संपर्क साधक श्री सूदन मौर्य का विशेष योगदान रहा।

पैक्स के प्राधिकृत अधिकारियों और प्रबंधकों को दिया गया प्रशिक्षण

दुर्ग। जिला सहकारी संघ दुर्ग द्वारा धमधा विकास खंड के पैक्स प्राधिकृत अधिकारी एवं प्रबंधकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण 31 मई को होटल गार्नेट इन दुर्ग में आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण में विकासखंड के 58 प्रशिक्षार्थी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण सत्र में राजेश साहू प्रशिक्षक द्वारा सहकारिता, सहकारी सिद्धांत, सहकार से समृद्धि योजना के बारे में बताकर बहुद्देशीय पैक्स की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए नूरपुर बेट मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसाइटी

नूरपुर जिला लुधियाना पंजाब का सचित्र उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उनके कार्यों एवं व्यवसाय बारे में विस्तार से बताया। नेतृत्व विकास पर भी इस दौरान चर्चा की गई। द्वितीय सत्र में पीएल सोनी प्रशिक्षक प्राधिकृत अधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य, सोसाइटी के बायलॉज,कर्मचारी सेवा नियम के संबंध में संक्षिप्त जानकारियां दी गई। सत्र में समस्त प्रशिक्षार्थियों को सहकारी समाचार भी वितरित करके उनकी समिति को ग्राहक बनने हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन जिला सहकारी संघ प्रबंधक कमलेश श्रीवास्तव द्वारा किया गया।

छिंद-कांसा टोकरी से गढ़ रही हैं आत्मनिर्भरता की नई कहानी

- छिंद-कांसा टोकरी से कोटानपानी की 100 से अधिक महिलाएं बना रही हैं परंपरा को पहान
- हर साल बन रही हैं लखपति दीदियां

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को गति देते हुए ग्रामीण आजीविका मिशन ''बिहान'' के अंतर्गत महिलाओं को स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसी दिशा में जशपुर जिले के काँसाबेल विकासखंड के आदिवासी बहुल कोटानपानी ग्राम पंचायत की महिलाओं ने छिंद और कांसा घास से बनी टोकरी को पहचान दिलाकर एक अनोखी सफलता की कहानी रच दी है।

कोटानपानी की महिलाएं अब पारंपरिक ज्ञान और हस्तशिल्प को आजीविका का आधार बनाकर अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। लगभग 100 महिलाएं छिंद और कांसा से टिकाऊ, सुंदर और आकर्षक टोकरियां बना रही हैं, जिनकी मांग न केवल जशपुर जिले में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों से भी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड और बिहान मिशन के सहयोग से इस पारंपरिक उत्पाद को राष्ट्रीय पहचान मिली है, और महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल हो चुकी हैं।

30 वर्षों पुरानी परंपरा को मिली नई दिशा–यह कला कोई नई नहीं, बल्कि लगभग 30 वर्ष पुरानी है। इसकी नींव रखी थी कोटानपानी की मन्मति नामक किशोरी ने, जिन्होंने 25 वर्ष पूर्व अपनी ननिहाल पगुराबहार (फरसाबहार विकासखंड) में यह कला सीखी और वापस अपने गांव में टोकरियों का निर्माण शुरू किया। शुरुआत में व्यक्तिगत उपयोग तक सीमित यह कला धीरे-धीरे अन्य महिलाओं तक पहुंची और स्थानीय बाजारों में इसकी बिक्री शुरू हुई। 2017 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व-सहायता समूहों के गठन के बाद इस पारंपरिक हुनर को संस्थागत रूप मिला। शुरुआत में हरियाली, ज्ञान गंगा और गीता नामक तीन समूह इस कार्य से जुड़े। फिर 2019 में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड के आगमन से महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण मिला। समूह की महिलाओं ने बिहान मेलों में भाग लेकर अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई, जिससे इस उत्पाद को पहचान मिली। जशप्योर ब्रांड के तहत बिक्री होने से देशभर से मांग आने लगी और महिलाओं की आय में जबरदस्त वृद्धि हुई।

प्राकृतिक और सांस्कृतिक पहचान वाला उत्पाद

छिंद (खजूर के पेड़ की सूखी पत्तियां) और कांसा –एक प्रकार की घास) से बनी यह टोकरी न केवल पर्यावरण अनुकूल है, बल्कि जशपुर के आदिवासी समाज में इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। विवाह, देवपूजन और छठ पूजा जैसे अवसरों पर इसका उपयोग किया जाता है। छिंद की पत्तियां सालभर उपलब्ध रहती हैं जबकि कांसा घास विशेष रूप से सावन-भादों में एकत्र कर सुरक्षित रखी जाती है। टोकरी निर्माण में छिंद को कांसा पर लपेटकर मजबूती और आकर्षक आकार दिया जाता है। ये टोकरियां पूजा सामग्री, फल अथवा उपहार स्वरूप उपयोग की जाती हैं।

आजीविका का सशक्त माध्यम बनी टोकरी– आज कोटानपानी की महिलाएं न केवल कच्चे माल का संग्रहण स्वयं करती हैं बल्कि प्रति किलोग्राम 150 रुपये की दर से कच्चा माल भी बेचती हैं। जिले के 15 से अधिक समूह इस कार्य से जुड़ चुके हैं, जिससे 100 से अधिक महिलाओं को सतत आजीविका मिली है। सरकारी सहयोग और महिलाओं के सामूहिक प्रयास से यह परंपरा अब पहचान बन चुकी है।

लखपति दीदी बनने की राह पर अग्रसर सरिता बाई

- लखपति दीदी बनने की राह पर
- बिहान समूह से मिली नई पहचान
- प्रधानमंत्री मुद्रा लोन से शुरू किया ईंट निर्माण कार्य, सालाना दो लाख रुपये तक की हो रही आमदनी

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ''बिहान'' योजना के तहत उल्लेखनीय कार्य हो रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जशपुर जिले की महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त होकर अपने और अपने परिवार के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।

इसी क्रम में जशपुर जिले के मनोरा विकासखंड के ग्राम चड़िया की सरिता बाई आज लखपति दीदी बनने की राह पर हैं। उन्होंने ''बिहान'' योजना से जुड़कर पहले सीएलएफके माध्यम से सीएफराशि प्राप्त की, और बाद में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत जशपुर की बड़ौदा बैंक से एक लाख रुपये का ऋण लेकर ईंट निर्माण का कार्य शुरू किया।

सरिता बाई बताती हैं कि समूह में शामिल होने के पहले वे आर्थिक रूप से बेहद कमजोर थीं। घर की चारदीवारी तक सीमित जीवन में बदलाव तब आया, जब उन्होंने स्व-सहायता समूह से जुड़ने का निर्णय लिया। समूह से उन्हें न केवल शासन की योजनाओं की जानकारी मिली, बल्कि आर्थिक सहयोग भी प्राप्त हुआ।

ईंट निर्माण कार्य की शुरुआत उन्होंने समूह से 60 हजार रुपये जोड़कर की। वर्तमान में वे कुल 1.6 लाख रुपये के निवेश से 70 हजार ईंटों का निर्माण कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य निर्माण कार्यों के चलते ईंट की बढ़ती मांग का लाभ उन्हें मिल रहा है। वे बताती हैं कि इस कार्य से उन्हें सालाना दो लाख रुपये तक की आमदनी हो रही है।

सतत देखभाल से सुपोषित हुई कृषा

- गृहभेंट, पोषण परामर्श और समर्पित प्रयासों से कुपोषित बालिका सामान्य श्रेणी में पहुंची

दुर्ग/ महिला एवं बाल विकास विभाग जिला दुर्ग द्वारा चलाए जा रहे कुपोषण मुक्ति अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। समुदाय में पोषण के प्रति लगातार बढ़ती जागरूकता के चलते अब कई कुपोषित बच्चों का वजन सामान्य स्तर की ओर बढ़ रहा है। ऐसा ही एक प्रेरणादायक उदाहरण ग्राम गनियारी की 2 वर्ष 6 माह की बालिका कृषा ठाकुर का है, जो अब कुपोषण से मुक्त होकर सुपोषण की ओर बढ़ चली है।

कृषा पूर्व में मध्यम कुपोषित श्रेणी में थी। जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिथिलेश देवदास ने गृहभेंट की, तो पता चला कि कृषा को बाजार के पैकेट वाले चिप्स, कुरकुरे आदि खाने की आदत थी, जिससे उसका वजन नहीं बढ़ रहा था। सामान्य वजन की श्रेणी में आने के लिए कृषा को 800 ग्राम वजन बढ़ाना था। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कार्यकर्ता ने परिवार को पोषण संबंधी उचित सलाह दी। उन्हें बताया गया कि पैकेट वाले खाद्य पदार्थ बच्चों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालते हैं। इसके स्थान पर घर में बना पौष्टिक भोजन, अंकुरित अनाज, मौसमी फल, चना, मूंगफली और रेडी-टू-ईट खाद्य का उपयोग करने को कहा गया। पर्यवेक्षक शशि रैदास द्वारा भी परिवार को डाइट चार्ट पढ़ाकर समझाया गया और उसका नियमित पालन करने की सलाह दी गई। साथ ही, कृषा को बाल संदर्भ योजना का लाभ दिलाया गया और आवश्यक दवाइयां भी समय पर दी गईं। लगातार चार माह के सतत प्रयासों और गृहभेंट के माध्यम से की गई निगरानी से कृषा का वजन 9.2 किलोग्राम से बढ़कर 10.2 किलोग्राम हो गया। कृषा अब सामान्य श्रेणी में आ गई है। उसकी मां ने बाल विकास विभाग और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के प्रति आभार जताया और अपने अनुभव को गाँव की अन्य माताओं के साथ साझा किया।

कृषा की कहानी से प्रेरित होकर एक अन्य कुपोषित बालक मितांशु साहू की मां ने भी यही उपाय अपनाने शुरू कर दिया। अब मितांशु को सामान्य स्थिति में आने के लिए केवल 200 ग्राम वजन बढ़ाने की आवश्यकता है। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी अजय कुमार साहू ने बताया कि कुपोषण से निपटने के लिए विभाग द्वारा कुपोषण मुक्त ग्राम पंचायतों में नियमित गृहभेंट, पोषण शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

कौशल प्रशिक्षण से ग्रामीण महिलाएं और युवा हो रहे आत्मनिर्भर

कौशल प्रशिक्षण से ग्रामीण महिलाएं और युवा हो रहे आत्मनिर्भर

कौशल प्रशिक्षण से ग्रामीण महिलाएं और युवा हो रहे आत्मनिर्भर

रायपुर। हमने कभी नहीं सोचा था कि गांव की महिलाएं भी राजमिस्त्री बन सकती हैं, यह कहते हुए ग्राम तुर्काडीह की ममता यादव की आंखों में आत्मविश्वास की चमक दिखाई देती है। ममता उन 22 महिलाओं में शामिल हैं जो इन दिनों बिलासपुर के कोनी स्थित एसबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी में राजमिस्त्री प्रशिक्षण में भाग ले रही हैं। अब वे सिर्फदीवारें नहीं बना रहीं, बल्कि अपने भविष्य की नींव भी मजबूत कर रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को व्यावसायिक दक्षता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने का कार्य यह संस्थान बखूबी कर रहा है। खासकर बीपीएल परिवारों के लिए यह एक वरदान साबित हो रहा है, जहां निःशुल्क आवास, भोजन और प्रशिक्षण की सुविधा मिल रही है। प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताते हुए कहती हैं कि सरकार की योजनाओं से अब ग्रामीण महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। यह बदलाव केवल कौशल तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं की सोच, आत्मनिर्भरता और सामाजिक स्थिति में भी सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है।

ग्राम मानिकपुरी की शांता मरावी बताती हैं कि उन्होंने स्व सहायता समूह से प्रशिक्षण की जानकारी मिलने पर तुरंत भाग लिया। वे कहती

हैं, यहां रहने और खाने की उत्तम व्यवस्था है और वह भी पूरी तरह निःशुल्क। इससे हम बिना चिंता के प्रशिक्षण पर ध्यान दे पा रहे हैं। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वे अपने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्य में काम कर आजीविका कमाना चाहती हैं।

संस्थान के निदेशक श्री नरेंद्र साहू ने बताया कि हर वर्ष 1000 से अधिक युवाओं और महिलाओं को यहां प्रशिक्षित किया जाता है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवारों को व्यावसायिक रूप से दक्ष बनाना है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें बैंकों से जोड़ा जाता है, ताकि वे स्वरोजगार के लिए ऋण प्राप्त कर सकें। संस्थान विभिन्न ट्रेडों जैसे- दर्जी, ब्यूटी पार्लर, मशरूम उत्पादन, पशुपालन, जैविक खेती, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, बेकिंग, कुकिंग, बागवानी, ज्वेलरी मेकिंग और मोबाइल रिपेयरिंग में प्रशिक्षण देता है।

पैक्स प्राधिकृत अधिकारी, प्रबंधकों को दिया गया नेतृत्व विकास पर प्रशिक्षण

दुर्ग। जिला सहकारी संघ दुर्ग द्वारा पाटन विकासखंड के पैक्स प्राधिकृत अधिकारी एवं प्रबंधकों का 1 जून को एक दिवसीय प्रशिक्षण होटल गार्नेट इन दुर्ग में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में विकासखंड के 60 प्रशिक्षार्थी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण सत्र में राजेश साहू प्रशिक्षक द्वारा सहकारिता, सहकारी सिद्धांत, नेतृत्व विकास, सहकार से समृद्धि योजना के बारे में बताकर बहुद्देशीय पैक्स की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कांगड़ी मल्टीपरपज सोसाइटी, नूरपुर बेट मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसाइटी नूरपुर जिला लुधियाना पंजाब का सचित्र उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उनके कार्यों एवं व्यवसाय के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही नेतृत्व विकास पर चर्चा की गई। द्वितीय सत्र में पीएल सोनी प्रशिक्षक प्राधिकृत अधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य, सोसाइटी के बायलॉज, कर्मचारी सेवा नियम के संबंध में संक्षिप्त जानकारियां दी गई। सत्र में समस्त प्रशिक्षार्थियों को सहकारी समाचार भी वितरित करके उनकी समिति को ग्राहक बनने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन जिला सहकारी संघ प्रबंधक कमलेश श्रीवास्तव द्वारा किया गया।

नारायणपुर। जिला नारायणपुर के ग्राम झारा के लैंपस भवन में कृषक भाइयों का प्रबंधकारणीय वर्ग का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ संभागीय कार्यालय जगदलपुर के तत्वावधान में प्रशिक्षक मितेश पानीग्राही द्वारा 26 से 28 मई तक किया गया। इस वर्ग में सदस्य भाइयों को सहकारिता का अर्थ, महत्व, सिद्धांत, उद्देश्य और विकास सहकारी ढांचा, आमसभा की ऱ्र्णनीति, व्यवसाय विकास, प्रबंधक के कार्य, अध्यक्ष- उपाध्यक्ष के कार्य आदि पर विस्तार से जानकारी दी गई। जिसे सफल बनाने में संघ के संपर्क साधक श्री करुणाकर मंडन का सहयोग सराहनीय रहा।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

ऑनलाईन सहकारी प्रबंध में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम सत्र क्रमांक -10 हेतु आवेदन आमंत्रित

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर में दिनांक **01 जुलाई 2025 से 20 अक्टूबर 2025 तक** ऑनलाईन सहकारी प्रबंध में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम सत्र 10 प्रारंभ होने जा रहा है। जिसमें प्रवेश हेतु आवेदन पत्र दिनांक **30 जून 2025** तक आमंत्रित है। प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाईन (जूम ऐप्प) संचालित किया जायेगा। उक्त ऑनलाईन डिप्लोमा सत्र प्रवेश हेतु प्रशिक्षण शुल्क रू. 3000/- (रूपये तीन हजार मात्र) निर्धारित है। डिप्लोमा सत्र में सहकारिता विभाग एवं सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी/प्रायवेट एवं शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियां प्रवेश ले सकेंगे, अभ्यार्थी (10+2) 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। स्नातक स्तर के प्रशिक्षार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। प्रशिक्षण शुल्क आप एनईएफटी / चेक के माध्यम से जमा कर सकते है, जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर के पक्ष में देय होगा।

आनलाईन फीस जमा करने के हेतु बैंक की जानकारीः भारतीय स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा एन.आई.टी, रायपुर, बैंक खाता क्रमांक 33624532896, आइएफएसी कोड- SBIN0002852

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करेंः-

1. प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, 14 पार्क स्ट्रीट-3, चौबे कालोनी रायपुर, फोन नं. 0771-4035702, मो. नं. 78798-17829, 93296-33236, 93031-33335, ईमेलः- cooptrainingcenter@gmail.com
2. हमारे वेबसाईट www.cgcoop.in में समस्त जानकारी उपलब्ध है।

(एन.आर.के. चन्द्रवंशी)
प्रबंध संचालक
छ.ग.राज्य सहकारी संघ मर्या.
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ में 5.52 लाख टन रासायनिक खाद का भंडारण

■ **डीएपी के विकल्प के बारे में किसानों को दी जा रही जानकारी**

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को खरीफ सीजन में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के 5.52 लाख टन रासायनिक उर्वरकों का भंडारण सुनिश्चित किया है। यह भंडारण प्रदेश की 2058 सहकारी समितियों एवं विपणन संघ के माध्यम से किया गया है, जिससे किसानों को समय पर और सुगमता से खाद उपलब्ध हो सके।

अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री केएन काण्डे ने बताया कि, राज्य की सहकारी समितियों में अब तक 4.62 लाख टन खाद का भंडारण किया जा चुका है, जिसमें से 2.44 लाख टन खाद का वितरण किसानों को किया जा चुका है। वर्तमान में समितियों में 2.18 लाख टन खाद उपलब्ध है, जिसमें प्रमुख रूप से 92,120 टन यूरिया, 47,451 टन सुपर फास्फेट, 19,885 टन डीएपी, 32,643 टन एन.पी.के. और 25,855 टन पोटाश शामिल हैं।

उपलब्ध कराए गए डीएपी के विकल्प

रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण डीएपी खाद की आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका को देखते हुए, राज्य सरकार ने अग्रिम तैयारी करते हुए एन.पी.के., सुपर फास्फेट और यूरिया खाद को विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया है। सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा किसानों को इन विकल्पों की प्रति एक उपयुक्त मात्रा के बारे में जानकारी दी जा रही है, ताकि किसान खरीफ सीजन में इसका उपयोग कर डीएपी की कमी को पूरा करते हुए बेहतर फसल उत्पादन कर सकें।

किसानों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता : कश्यप

सहकारिता मंत्री श्री कश्यप ने कहा है कि, किसानों के हितों की रक्षा और कृषि उत्पादन की निरंतरता छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा लक्ष्य है कि हर किसान को समय पर गुणवत्तायुक्त खाद उपलब्ध हो और राज्य की खेती उन्नति की दिशा में आगे बढ़े।

मंत्री ने दिए उर्वरकों के स्टाक रखने के निर्देश

सहकारिता मंत्री श्री कश्यप ने विपणन संघ के सभी प्रदाय केंद्रों को निर्देशित किया है कि, जून-जुलाई के दौरान कम से कम 100 टन यूरिया, 100 टन डीएपी/एन.पी.के., 100 टन सुपर फास्फेट और 50 टन पोटाश खाद का स्टॉक अनिवार्य रूप से बनाए रखें। इसी प्रकार, सभी सहकारी समितियों को प्रति केंद्र 10-10 टन यूरिया, एन.पी.के./डीएपी और सुपर फास्फेट खाद का भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे खाद की निरंतर आपूर्ति बनी रहे। राज्य में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, खाद भंडारण एवं वितरण की स्थिति की दैनिक समीक्षा की जा रही है। साथ ही, निजी व्यापारियों द्वारा की जा रही खाद बिक्री की सतत निगरानी, गुणवत्ता की जांच और निर्धारित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश कृषि विभाग को दिए गए हैं।

राष्ट्रीय आम महोत्सव से आम उत्पादन के लिए प्रेरित होंगे छत्तीसगढ़ के किसान : कृषि मंत्री श्री नेताम

■ कृषि विश्वविद्यालय में चार दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का समापन

रायपुर। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राम विचार नेताम ने आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में आयोजित चार दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव के समापन समारोह मे शामिल हुए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रकृति की ओर सोसायटी के संयुक्त के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित चार दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का समापन 09 जून को हुआ।

समापन समारोह के मुख्य अतिथि कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रामविचार नेताम थे। वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष श्री चन्द्रहास चन्द्राकर, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अध्यक्ष श्री राम प्रताप सिंह तथा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री आर.एस. विश्वकर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

समारोह की अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने की। इस अवसर पर राष्ट्रीय आम महोत्सव में लगाई गई आम प्रदर्शनी के अंतर्गत विभिन्न आम प्रजातियों में पुरस्कार प्राप्त करने वाले आम उत्पादक किसानों तथा संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया। छत्तीसगढ़ में आम उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रगतिशील कृषकों को भी सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय आम महोत्सव में 1600 से अधिक आमों की प्रदर्शनी

राष्ट्रीय आम महोत्सव का समापन करते हुए कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित इस वृहद एवं भव्य राष्ट्रीय आम महोत्सव में छत्तीसगढ़ के किसानों एवं आम नागरिकों को 1600 से अधिक आमों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा राज्य शासन का संचालनालय उद्यानिकी धन्यवाद का पात्र है। उन्होंने कहा कि यहां आकर अनेक नई-नई किस्मों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों को भी आम की नई-नई उन्नत एवं विभिन्न गुणों से परिपूर्ण प्रजातियों के बारे में जानने का मौका मिला। इसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ के किसान आम की नई प्रजातियों के उत्पादन के लिए प्रेरित होंगे। श्री नेताम ने आम की नवीन उन्नत किस्मों के विकास के लिए देश के कृषि वैज्ञानिकों को बधाई दी। श्री नेताम ने कहा कि इस तरह के आयोजन राजधानी रायपुर के अलावा बस्तर एवं सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल संभागों में भी आयोजित किये जाने चाहिए जिससे इन आदिवासी अंचलों के किसानों को भी लाभ मिल सके। श्री नेताम ने कहा कि आम महोत्सव में भारत के विभिन्न राज्यों की लोकप्रिय आम प्रजातियों के साथ ही बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों से 120 आम प्रजातियां शामिल की गई हैं जो छत्तीसगढ़ में आम की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय तथा उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को छत्तीसगढ़ में आम उत्पादन को और अधिक प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये।

किसानों एवं आम नागरिकों ने क्रय किये लगभग 50 हजार पौधे

समारोह की अध्यक्षता करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने राष्ट्रीय आम महोत्सव के बारे में मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों को जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय आम महोत्सव में आम की 427 से अधिक किस्मों के 1200 से अधिक प्रादर्श एवं आम से बने 56 तरह के व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। विगत तीन दिनों में राष्ट्रीय आम महोत्सव में 10 हजार से अधिक लोगों ने मेले एवं प्रदर्शनी का अवलोकन किया। देश के विभिन्न हिस्सों से आए आम उत्पादकों द्वारा आम के विभिन्न किस्मों के फलों तथा पौधों का विक्रय भी किया गया जहां किसानों एवं आम नागरिकों द्वारा लगभग 50 हजार पौधे क्रय किये गये। मेले में बड़ी संख्या मात्रा में विभिन्न आम प्रजातियों के फलों का विक्रय भी किया गया। डॉ. चंदेल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय परिसर में लगातार दूसरी बार आयोजित यह राष्ट्रीय आम महोत्सव सभी मायनों में काफी सफल रहा।

प्रगतिशील कृषक हुए सम्मानित

इस अवसर पर अतिथियों द्वारा छीसगढ़ में आम के उत्पादन हेतु विशिष्ट योगदान देने वाले प्रगतिशील कृषकों - श्री सुरेश गुप्ता ग्राम सिलफिली, जिला अबिकापुर, श्री तोरन लाल ध्रुव ग्राम बारूका जिला गरियाबंद और श्री सुरेश ठाकुर ग्राम चंदनीडीह जिला रायपुर को समानित किया गया। कार्यक्रम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग तथा उद्यानिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कृषि वैज्ञानिक तथा बड़ी संया में आम उत्पादक किसान उपस्थित थे।

अबूझमाड़ के कुतुल तक पहुँची बस सेवा

■ ग्रामीणों में दिखा उत्साह, मुख्यमंत्री का जताया आभार

■ नियद नेल्ला नार योजना से बदल रही गांवों की तस्वीर

■ ग्रामीणों में दिखा उत्साह, मुख्यमंत्री का जताया आभार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित अबूझमाड़ क्षेत्र में विकास की नई रफ्तार देखने को मिल रही है। नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत नारायणपुर जिले के अंदरूनी इलाकों में 14 नवीन पुलिस कैंपों की स्थापना के बाद वहां सड़क, पुल-पुलियों एवं मोबाइल कनेक्टिविटी का तेज़ी से विस्तार हो रहा है।

इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा 13 मई 2025 को पहली बार ग्राम कुतुल तक नारायणपुर से सीधी बस सेवा प्रारंभ की गई। यह बस सेवा जिला मुख्यालय से लगभग 49 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कुतुल के साथ-साथ कुरूषनार, बासिंग, कुंदला, कोहकामेटा, ईरकभट्टी, कच्चापाल और कोडलियर जैसे दूरस्थ गांवों को भी जोड़ रही है। बस सेवा शुरू होने से ग्रामीणों में विशेष उत्साह का माहौल है।

पहले इन गांवों के लोग पगडंडियों के सहारे आवागमन करते थे। बारिश के मौसम में नदियों और नालों के उफान पर होने से

मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना अत्यंत कठिन होता था। कई बार ग्रामीणों को बीमार व्यक्ति को कंधे पर उठाकर अस्पताल तक लाना पड़ता था। अब बस सेवा शुरू होने से न केवल आवागमन सुगम हुआ है, बल्कि ग्रामीणों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति और प्रशासनिक कार्यों के लिए नारायणपुर तक समय पर पहुंचने की सुविधा भी मिल रही है। इसी तरह नारायणपुर से मसपुर तक भी 14 गांवों के लिए बस सेवा शुरू की गई है, जिससे इन इलाकों के लोगों को जिला मुख्यालय से बेहतर संपर्क मिला है। योजना के तहत 4जी मोबाइल टॉवर भी लगाए गए हैं, जिनसे ग्राम कस्तुरमेटा, मसपुर,

ईरकभट्टी, मोहन्दी, होरादी, गारपा और कच्चापाल के लोग अब मोबाइल नेटवर्क से जुड़ पा रहे हैं। इससे न केवल संचार व्यवस्था में सुधार हुआ है, बल्कि शैक्षणिक, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सेवाओं की पहुँच भी बेहतर हुई है।

ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों के बाद अब उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। नियद नेल्लानार योजना ने उनके जीवन में नया प्रकाश फैलाया है।

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025, प्रदेश के जिलों में विविध स्वरूपों में कार्यक्रमों का आयोजन

महिला सशक्तिकरण की दिशा में दिया गया प्रशिक्षण

धमतरी। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत जिले के महिला स्व सहायता समूह के सामुदायिक संवर्ग (सीआरपी) / सदस्य के रोजगार सृजन के लिए जीएसटी, टीडीएस रिटर्न, आयकर एवं लेखांकन कार्य संबंधी पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रथम दिवस का शुभारंभ बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान कलेक्ट्रेट परिसर कंपोजिट भवन के पास (आईसीटी) में संपन्न हुआ।

जिला प्रशासन तथा सहकारिता विभाग के जिला सहकारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सहकारिता उपायुक्त धमतरी प्रदीप ठाकुर, जिला परियोजना प्रबंधक जय वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रवण गोयल व आशुतोष मिश्रा, स्टेट जीएसटी शैलेंद्र ठाकुर, ए जे लकरा, संघ के प्राधिकृत अधिकारी सीपी साहू, संघ प्रबंधक ए पी गुप्ता, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ रायपुर के प्रशिक्षक एस के पटेल, सहकारी निरीक्षक अरविंद मिश्रा, तोषी भूआर्य, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक पूर्णिमा घाणेकर, सहकारिता विस्तार अधिकारी नगरी एनसी देव तथा सीईओ धमतरी संगीता सिन्हा की गरिमामयी उपस्थिति में दीप प्रज्वलन व मां भारती के चित्र पर पूजन अर्चन कर किया गया।

अफसरों ने बताए आयोजन के उद्देश्य

कार्यक्रम के प्रारंभ में उपायुक्त सहकारिता प्रदीप ठाकुर ने कहा कि, यह कार्यक्रम जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में यह प्रथम लेखा व जीएसटी प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। प्रबंधक जिला परियोजना जय वर्मा ने कहा कि, महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत मत्स्य, बुनकर आदि अन्य समितियो का लेखांकन निष्पादन हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता खेती है। इस प्रशिक्षण से अधिकाधिक लाभ उठाने उन्होंने प्रशिक्षार्थियों से अपील की। श्री गोयल ने जीएसटी, टीडीएस संबंधी बेसिक जानकारी से अवगत कराया। लेखा प्रशिक्षक श्री पटेल ने लेखांकन का सामान्य परिचय, इतिहास एवं आधुनिक लेखा पद्धति जिसमें दोहरा लेखा प्रणाली, वाउचर, जनरल एंट्री एवं विभिन्न प्रकार के सहकारी समितियो में रखे जाने वाले अनिवार्य पुस्तक एवं प्रशासनिक रजिस्टर के बारे में प्रोजेक्टर के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम में चयनित महिला समूह के पूरे सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एनसी देव सहकारिता विस्तार अधिकारी नगरी ने किया।

मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्यों को दिया गया लेखांकन प्रशिक्षण

धमतरी। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान" के तहत जिले के चार विकासखंड से चयनित सीआरपी, आरबीके/ समूह के सदस्य हेतु पांच दिवसीय जीएसटी, टीडीएस रिटर्न, आयकर एवं लेखांकन संबंधी प्रशिक्षण बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान धमतरी में संपन्न हुआ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय दिवस 3 जून को प्रथम कालखंड 11:00 बजे पूर्वाह्न से 1:30 बजे तक प्रशिक्षक चार्टर्ड अकाउंटेंट आशुतोष मिश्रा ने जीएसटी पंजीयन, रिटर्न फाइल, जीएसटी बिल बनाने, स्लैब रेट सहित टीडीएस, टीसीएस के बारे में बेसिक जानकारी प्रोजेक्टर के माध्यम से दिया। लेखांकन प्रशिक्षक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ रायपुर के व्याख्याता सुरेश पटेल ने द्वितीय कालखंड 2:00 बजे से 4:30 बजे तक प्रोजेक्टर के माध्यम से दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत खाते के प्रकार और उसके वर्गीकरण को विस्तार पूर्वक बताया, साथ ही मत्स्य सहकारी समितियो में होने वाले लेनदेन आदि की जर्नल प्रविष्टियो की जानकारी से प्रशिक्षार्थियों को अभ्यास कराया गया।

आयकर और टीडीएस की दी गई जानकारी

चार्टर्ड अकाउंटेंट आशुतोष मिश्रा ने जीएसटी, आयकर व टीडीएस पर विस्तार पूर्वक प्रोजेक्टर के माध्यम से जीएसटी स्लैब से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिटर्न दाखिल करने के प्रकार, रिटर्न भरने की अवधि के साथ ही आरसीएम (रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म) सहित जीएसटी स्लैब की जानकारी दी तथा प्रशिक्षार्थियों से अभ्यास भी कराया गया। चतुर्थ दिवस 5 जून 2025 पर चार्टर्ड अकाउंटेंट आशुतोष मिश्रा द्वारा जीएसटी, टीडीएस सहित आयकर पोर्टल में पंजीयन की विधि, फार्म 26 की जानकारी प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षित कर प्रशिक्षार्थियों से अभ्यास कराया गया।

स्वसहायता समूह की महिलाओं की रही भागीदारी

कार्यक्रम में जिले के महिला स्वसहायता समूह के सभी चयनित महिलाओं सहित उपायुक्त सहकारिता प्रदीप ठाकुर, सहकारी निरीक्षक अरविंद मिश्रा तथा संघ प्रबंधक एपी गुप्ता उपस्थित रहे।

समूहों से चयनित महिलाओं को दिया गया जीएसटी, आयकर और लेखांकन का प्रशिक्षण

धमतरी। जिले के महिला स्वसहायता समूह के सामुदायिक संवर्ग के चयनित सदस्यों का रोजगार सृजन के उद्देश्य से आयोजित पांच दिवसीय लेखांकन, जीएसटी, टीडीएस और आयकर पर प्रशिक्षण 6 जून 2025 को संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान" के तहत माननीय कलेक्टर के दिशा निर्देश के परिपालन में जिला प्रशासन व सहकारिता विभाग के जिला सहकारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में "अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025" के अंतर्गत यह कार्यक्रम बड़ौदा आरसेटी भवन में आयोजित किया गया।

समापन दिवस पर अफ़सरों की रही मौजूदगी

समापन दिवस के कार्यक्रम में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा, उपायुक्त सहकारिता प्रदीप ठाकुर, बड़ौदा आरसेटी निदेशक सुश्री अनीता टुडू व जग्येश्वर समल, जिला सहकारी संघ के प्राधिकृत अधिकारी सीपी साहू, संघ प्रबंधक एपी गुप्ता, सहकारी निरीक्षक एके मिश्रा व भुनेश्वर नेताम, चार्टर्ड अकाउंटेंट आशुतोष मिश्रा, व्याख्याता सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय रायपुर एस के पटेल उपस्थित रहे। माननीय कलेक्टर ने प्रशिक्षार्थियों से परिचय प्राप्त कर दिए जा रहे प्रशिक्षण की जानकारी ली, जिसमें प्रशिक्षार्थियों द्वारा प्रशिक्षण अवधि बढ़ाने निवेदन करने पर उन्होंने सकारात्मक कार्यवाही करने आश्वस्त किया।

समझाई गई जीएसटी पंजीयन की विधि

कार्यक्रम में सहकारी निरीक्षक अरविंद मिश्रा ने सहकारी समिति के पंजीयन संबंधी जानकारी के साथ ही जिला स्तरीय बिहान सहकारी समिति के गठन पर प्रशिक्षार्थियों को अवगत कराया। समापन दिवस पर चार्टर्ड अकाउंटेंट आशुतोष मिश्रा ने जीएसटी पंजीयन की विधि, टीडीएस रिटर्न के प्रकार तथा लेखांकन प्रशिक्षण एस के पटेल ने बैंक समाधान विवरण व मूल्य ह्रास पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रोजेक्टर के माध्यम से देकर प्रशिक्षार्थियों को अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम के अंत में सहकारिता उपायुक्त प्रदीप ठाकुर ने समापन दिवस 6 जून 2025 पर सभी प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र व ग्रुप फेटोग्राफ का वितरण कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी एवं संघ प्रबंधक द्वारा कार्यक्रम समापन की घोषणा की गई।

सुपर फुड मुनगा से महिलाओं को रही लाखों की कमाई

- सुपर फुड मुनगा से कोकड़ी की महिलाओं को रही लाखों की कमाई
- राजधानी रायपुर में हो रही सप्लाई
- अन्य लोगों को अपने अभिनव प्रयोग का दे रहीं प्रशिक्षण

रायपुर। औषधीय गुणों से भरपूर सुपर फुड मुनगा की फसल लेकर धमतरी जिले के ग्राम कोकड़ी की महिलाएं अपनी आमदनी दुगुना कर रहीं हैं। मुनगा को सब्जी के तौर पर तो उपयोग किया ही जाता है। इसके साथ ही मुनगे की पत्तियों का पावडर मल्टीविटामिन सप्लीमेंट के साथ ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और बीपी को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। यही वजह है कि महिलाएं मुनगा की बिक्री ना केवल आसपास के बाजारों में कर रहीं हैं, बल्कि राजधानी रायपुर में भी इसकी सप्लाई कर रहीं हैं। इससे उन्हें दुगुनी आमदनी मिल रही है।

सरकार में मिल रही है मदद–धमतरी जिले के कुरूद विकासखण्ड स्थित ग्राम पंचायत कोकड़ी की जय मां लक्ष्मी स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती रामेश्वरी साहू बतातीं हैं कि उनके समूह में 12 सदस्य हैं, जो मिल-जुलकर मुनगे की खेती कर रहीं हैं। उन्होंने बताया कि गांव के खाली पड़े लगभग साढ़े तीन एकड़ से अधिक की भाठा जमीन पर मिश्रित खेती करने के लिए उन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 11 लाख 44 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति मिली। इसके बाद महिलाओं ने इस भाठा जमीन पर साल भर मेहनत किया और उनके द्वारा लगाए गए पौधे लहलहाने लगे। इन पौधों में मुनगा के अलावा करौंदा, आंवला और नींबू के पौधे शामिल हैं। मुनगे के पेड़ों में फल जल्दी लगने लगे और साल में दो फसल मिलने लगी। इससे महिलाओं को दुगुनी आय मिल रही है। श्रीमती साहू बताती हैं कि उनके इस अभिनव प्रयोग को देखने के लिए जिले के अन्य गांव के लोग भी आते हैं और उनसे इसका प्रशिक्षण भी लेकर जाते हैं।

आजकल खेती के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है और आधुनिक तरीके से भी लोग खेती कर रहे हैं। धान, गेहूं, दलहन-तिलहन के अलावा अब लोग सब्जियों की फसल लेने में आगे आ रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। मुनगा का पौधा किसी भी जमीन पर आसानी से उगने और कम पानी में भी जल्द फल देने वाला पौधा है। इसमें प्रोटिन, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन बी, सी और ए की मात्रा भरपूर होती है। मुनगा के जड़, छाल, फूल, पत्तियां और फल सभी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। यह सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि सेहत से भी सीधा रिश्ता रखता है।

मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना ने बदली पार्वती मिझी की ज़िंदगी : बेटियों के सपनों को मिली उड़ान

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के शांत और खूबसूरत गांव धमधा में सूरज तप रहा था और दोपहर के समय हर कोई अपने घरों में आराम कर रहा था, लेकिन 40 वर्षीय पार्वती मिझी और उनके पति काम में लगे हुए थे। पार्वती ने अपने सिर को दुपट्टे से ढका, अपनी कमीज को साड़ी के ऊपर से नीचे किया और काम जारी रखा। काम के बीच उन्होंने एक पल अपनी पांच बेटियों के बारे में सोचने के लिए निकाला। वे अच्छी लड़कियां हैं, उन्होंने सोचा, मुझे यकीन है कि वे अपना स्कूल का काम पूरा कर रही होंगी। यह सोचते ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई।पार्वती ने खुद गरीबी में जीवन बिताया था और उन्हें कभी अवसर नहीं मिले, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को इस दलदल से बाहर निकालने का दृढ़ निश्चय कर रखा था। जब उनकी दो बड़ी बेटियों ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा अच्छे अंकों से पास की, तो पार्वती ने फैसला किया कि उन्हें न्याय मिलना ही चाहिए।

जब उन्हें पंचायत द्वारा समर्थित श्रम संसाधन केंद्र के बारे में पता चला, तो वह बिना देर किए संभावित वित्तीय सहायता योजनाओं के बारे में पूछताछ करने के लिए दौड़ पड़ीं। पार्वती और उनके पति ने तब राहत की सांस ली, जब उन्हें मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के बारे में जानकारी मिली। यह योजना पंजीकृत भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

सीएम कैंप कार्यालय में दिव्यांग प्रदीप को मिली बैटरी चलित ट्राई सायकल

जशपुरनगर। ट्राइसाइकिल पाकर दिव्यांग प्रदीप श्रीवास की खुशी बता रही है जैसे जीवन में उन्हें एक नया सहारा मिल गया है। अब वे अपने कुछ कामों को खुद से अंजाम दे सकते हैं। प्रदीप दोनों पैरों से चलने-फिरने में असमर्थ थे। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले फरसाबहार निवासी प्रदीप को इससे उनके समान्य दिनचर्या में भी काफी कठिनाईयों को सामना करना पड़ता था। उन्होंने अपनी परेशानियों का जिक्र करते हुए मदद के लिए सीएम कैम्प कार्यालय में आवेदन दिया।

मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में आज उन्हें बैटरी चलित ट्राइसाइकिल प्रदान की गई। ट्राइसाइकिल पाकर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और सीएम कैंप कार्यालय का आभार व्यक्त किया है। सीएम कैंप कार्यालय बगिया मानवीय संवेदनाओं का केंद्र बन गया हैं। कैंप कार्यालय शासन की योजनाओं का आम जनता को लाभ दिलाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के साथ ही असहाय, पीड़ितों और जरूरतमंदों को हर संभव मदद करने प्रयासरत है, ताकि समाज के हर वर्ग को न्याय मिल सके।

नरेगा से जल संरक्षण, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी और ग्रामीणों को मिला आर्थिक संबल

रायपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सूरजपुर जिले के भैयाथान जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत खाड़ापारा, कंवरा एड भवराही में मनरेगा योजना के तहत जल संरक्षण, सिचाई सुविधा विस्तार और आजीविका सुदृढीकरण हेतु क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। ग्रामीणों की आवश्यकताओं और स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन एवं पंचायतों के समन्वय से विभिन्न जल संरचनाओं का निर्माण किया गया, जिससे न केवल जल संकट पर काबू पाया गया, बल्कि कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिली।

ग्राम पंचायत खाडापारा में अम्बर के खेत के पास नाले पर मिट्टी बांध निर्माण कार्य मनरेगा के तहत किया गया, जिससे लगभग 5 एकड अतिरिक्त भूमि सिंचित होने लगी है। पूर्व में वर्षा पर निर्भर किसानों को अय रबी सीजन में भी सरसों, गेहूं व सब्जियों की खेती का अवसर मिला है, जिससे 30 से अधिक किसान लगभग 20 से 25 हजार रुपये की अतिरिक्त वार्षिक आय अर्जित कर रहे हैं। यह मिट्टी बाध न केवल सिचाई सुविधा उपलब्ध करा रहा है, बल्कि भूजल स्तर में सुधार और मिट्टी के कटाव को भी रोकने में सहायक सिद्ध हो रहा है।

वहीं ग्राम पंचायत केंवरा के कोदुमुड़ा नाले में मिट्टी के चेक डेम का निर्माण एक सामुदायिक पहल के रूप में सामने आया है। यह सरचना वर्षा जल को संग्रहीत कर अपवाह को नियंत्रित करती है और भूजल को पुनर्भरण प्रदान करती है. जिससे स्थानीय किसानों को साल भर सिंचाई जल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। इससे खेती की उत्पादकता में इजाफा हुआ है. पशुधन पालन में सुधार आया है तथा परिवारों की आय में स्थायित्व आया है। चेक डैम ने ग्रामीणों को जलवायु अनिश्चितता के खिलाफ मजबूत लचीलापन प्रदान किया है।

इसी क्रम में ग्राम पंचायत भवराही में श्री रामाधार/रामसरन के खेत में मनरेगा के तहत खेत तालाब (डबरी)का निर्माण किया गया, जिससे वर्षा जल का संचयन कर किसानों को समय पर सिंचाई सुविधा मिलने लगी है। निर्माण से पूर्व रामाधार वर्षा पर पूर्णतः निर्भर थे और कम उत्पादन के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। डबरी निर्माण के बाद उन्होंने धान के साथ-साथ मक्का, जेठी धान एवं सब्जी की खेती शुरू की, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। साथ ही मछली पालन जैसे वैकल्पिक कृषि कार्यों की संभावनाएं भी साकार हो रही है।

इन तीनों कार्यों ने मिलकर न केवल जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ अर्जित की हैं. बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, कृषि विकास और सतत आजीविका सुनिश्चित कर मनरेगा की प्रभावशीलता को सिद्ध किया है। जनपद भैयाथान की ये जल संरचनाएँ ग्रामीण विकास की एक सफल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आई हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों की सुरक्षा के साथ एक समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

छाती सोसाइटी में इफको ने दिया किसानों को प्रशिक्षण

धमतरी। ग्रामीण सेवा सहकारी समिति छाती में 3 जून को कृषि उपज मंडी प्रांगण छाती में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा किसानों को प्रशिक्षण एवं मिलने वाली सुविधाओं, और लाभों के बारे में जानकारी दी गई।

विकसित संकल्प यात्रा योजना कार्यक्रम कृषि विभाग धमतरी के अंतर्गत एवं इफ्को और इफ्को एमसी धमतरी के माध्यम से यह कार्यक्रम समिति छाती के द्वारा आयोजित किया गया था। जिसमें मत्स्य विभाग, पशु विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे। जिसमें छाती, उड़ेना, झिरिया, सरसों पूरी, डाही, संबलपुर, बोडरा, भोथली, कंडेल, देमार आदि गांव से जनप्रतिनिधि एवं किसान उपस्थित थे।

उर्वरकों के उपयोग की विधि बताई गई

इफ्को के द्वारा किसानों को नैनो युरिया, नैनो डीएपी का उपयोग करने के लिए विधि बताई गई। इफ्को एमसी के द्वारा कीटनाशक एवं निंदा नाशक दवाई का उपयोग करने के लिए जानकारी दी गई। मत्स्य विभाग, पशु विभाग, कृषि विभाग, समिति छाती आदि विभागों के द्वारा उपस्थित किसानों को विस्तृत जानकारी एवं शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं एवं लाभों के बारे में जानकारी दी गई। दवा छिडक़ाव के लिए ड्रोन का भी संचालन करके मंडी में दिखाया गया।

इनकी रही विशिष्ट मौजूदगी

कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के सरपंच सहित पंचगण छाती समिति के अध्यक्ष श्री ललित कुमार साहू, संबलपुर के अध्यक्ष बोडरा समिति के अध्यक्ष, सहित पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बाला राम साहू, प्रीतम साहू भोथली महामंत्री शाखा सम्बलपुर सुपर वाईजर और सभी प्रबंधक उपस्थित थे। उक्त जानकारी नरेंद्र कुमार साहू समिति प्रबंधक छाती ने दिया।

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ संभागीय कार्यालय जगदलपुर के तत्वावधान में जिला नारायणपुर के ग्राम कोकोड़ी के लैंपस भवन में कृषक भाइयों का सदस्य वर्ग का आयोजन प्रशिक्षक मितेश पानीग्राही द्वारा 23 व 24 मई को किया गया। जिसमें सहकारिता का अर्थ, महत्व, सिद्धांत, उद्देश्य, सदस्यता सदस्य के अधिकार, कर्तव्य बैठकें आमसभा, ऋणनीति, व्यवसाय विकास आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। जिसको सफल बनाने में संघ के संपर्क साधक श्री करुणाकर मंडन का सहयोग सराहनीय रहा।

धमतरी जिले में 11 करोड़ की चना खरीदी : नरेन्द्र

रायपुर। माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ने सहकारी समितियों एवं किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए 1 मार्च से 31 मयी तक लगभग 2197 किसानों से 20,646 कुंटल 11 करोड़ 66 लाख की चना खरीदी 5650 प्रति कुंटल की दर से जिले के आठ समितियों के द्वारा सफलतापूर्वक चना खरीदी किया गया। इससे किसान सहित सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी । आने वाले वर्ष में जल संरक्षण हेतु अधिक से अधिक धान फसल के जगह किसान दलहन तिलहन लगाने की और अवश्य अग्रसर होंगे।। सहकारी समितियों से चना खरीदी करने पर सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिला धमतरी जिला संगठन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, प्रशासन जिला प्रशासन सहित माननीय प्रधानमंत्री, सहकारिता मंत्री जी को आभार एवं धन्यवाद किया गया है ।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बना राजेंद्र के सपनों का आधार

- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बना राजेंद्र के सपनों का आधार,**
- **शुरू किया सेंटरिंग प्लेट व्यवसाय**
- **09.5 लाख की ऋण सहायता से शुरू किया व्यवसाय, अब अर्जित कर रहे नियमित आय**

महासमुंद। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी और प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें एक निश्चित प्रतिशत तक अनुदान (सब्सिडी) भी प्रदान किया जाता है।

इसी योजना के तहत महासमुंद विकासखंड के ग्राम खरोरा निवासी श्री राजेंद्र चंद्राकर ने लाभ प्राप्त किया। श्री चंद्राकर ने स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है। शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् उन्होंने नौकरी की बजाय स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने का निश्चय किया, ताकि वे स्वावलंबी बन सकें। हालांकि, व्यवसाय की शुरुआत के लिए उनके पास आवश्यक पूंजी की कमी थी, जिससे उनका सपना साकार नहीं हो पा रहा था। इसी दौरान उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जिसने उनके लिए एक नई राह खोल दी।

सी योजना का लाभ उठाने के उद्देश्य से श्री चंद्राकर ने खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, जिला पंचायत महासमुंद से संपर्क किया। उन्होंने विभाग से योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की, जिसमें उन्हें योजना के अंतर्गत पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, अनुदान की सीमा, ऋण की शर्तें, एवं व्यावसायिक गतिविधियों की सूची जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गईं। विभाग की मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार श्री चंद्राकर ने निर्धारित प्रारूप में अपना ऋण प्रकरण तैयार कर आवेदन जमा किया।

उनका ऋण आवेदन खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा औपचारिक रूप से पंजाब नेशनल बैंक, महासमुंद शाखा को अग्रेषित किया गया। बैंक द्वारा श्री राजेंद्र के ऋण प्रकरण की विधिवत समीक्षा एवं मूल्यांकन के पश्चात उन्हें 9,50,000 की ऋण सहायता स्वीकृत की गई।

इस आर्थिक सहायता का उपयोग करते हुए श्री राजेंद्र ने निर्माण कार्यों में उपयोग आने वाली लकड़ी की सेंट्रिंग प्लेटों की खरीदारी की। उन्होंने इन प्लेटों को स्थानीय शासकीय निर्माण कार्यों तथा निजी ठेकेदारों को किराये पर देना प्रारंभ किया। वर्तमान में वे प्रति फीट 05 रुपए की दर से सेंट्रिंग प्लेटों को किराए पर उपलब्ध कराते हैं। इनका उपयोग शासकीय भवन निर्माण तथा निजी निर्माण कार्यों में किया जाता है। सस्ती और सुलभ दरों के कारण इनकी मांग लगातार बनी हुई है, जिससे राजेंद्र को नियमित आय प्राप्त हो रही है और उनका व्यवसाय धीरे-धीरे सफलतापूर्वक विस्तार की ओर अग्रसर है। वर्तमान में श्री चंद्राकर इस केंद्र के माध्यम से प्रतिमाह लगभग 30 से 35 हजार की आय अर्जित कर रहे हैं। साथ ही वे ऋण की मासिक किश्तों का समय पर और नियमित रूप से भुगतान कर रहे हैं। जिससे उनकी वित्तीय साख भी मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से श्री चंद्राकर न केवल अपनी आजीविका चला रहे हैं, बल्कि समाज में सम्मानजनक जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं।

युक्तियुक्तकरण से जशपुर के ग्रामीण अंचलों में शिक्षा की फिर से जली लौ

- **शिक्षकों की पदस्थापना से स्कूलों में लौटी रौनक**
- **पालकों में उत्साह, बच्चों में नया जोश**

रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और स्कूलों में शिक्षक उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में चलाए जा रहे युक्तियुक्तकरण अभियान के सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में क्रियान्वित इस अभियान से खासकर आदिवासी बहुल और दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में शिक्षा के क्षेत्र में नई उम्मीद जगी है।

फरसाबहार विकासखंड के दो ऐसे प्राथमिक विद्यालय रैंगारमुंडा और मुण्डाडीह, जो वर्षों से शिक्षक विहीन थे, अब यहां युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत 2-2 नियमित शिक्षकों पदस्थ हो चुके हैं। रैंगारमुंडा शाला, जो कि स्वयं मुख्यमंत्री श्री साय के विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी में स्थित है, में दो शिक्षकों की नियुक्ति से गांव में शिक्षा के प्रति वातावरण पूरी तरह से बदल गया है। पूर्व में विद्यालय केवल व्यवस्था अनुसार शिक्षकों के भरोसे चल रहा था, और बच्चों की उपस्थिति नगण्य थी। अब यहां के पालकों में नया विश्वास जगा है और वे पुनः अपने बच्चों का नामांकन स्थानीय शाला में कराने के लिए आगे आ रहे हैं।

इसी प्रकार मुण्डाडीह के प्राथमिक विद्यालय में लंबे समय से शिक्षक न होने के कारण शिक्षण कार्य लगभग ठप था। गांव के लोग आशंकित थे कि कहीं उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय न हो जाए। किंतु अब नियमित शिक्षकों की पदस्थापना से विद्यालय में फिर से पढ़ाई हो सकेगी। विद्यालय की शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और ग्रामवासियों ने शिक्षकों के आगमन पर उनका आत्मीय स्वागत किया और शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

ग्रामवासी श्रीमती शांति चौहान, जिनकी बेटी कक्षा पाँचवीं में पढ़ती है, भावुक होकर बताती हैं किअब हम निश्चिंत हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़-लिखकर कुछ बन पाएंगे। शिक्षक आ गए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है।

इस सकारात्मक बदलाव पर माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि शिक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। मैं स्वयं देख रहा था कि कई विद्यालय शिक्षक विहीन स्थिति में थे, विशेष रूप से सुदूर अंचलों में। इसलिए हमने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता से लागू किया। यह सुनिश्चित किया गया कि जहां-जहां जरूरत है, वहां शिक्षकों की तैनाती हो। जशपुर के फरसाबहार क्षेत्र में जो सकारात्मक बदलाव आ रहा है, वह इस नीति की सफलता का प्रमाण है। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में किया गया प्रयास है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी कहा कि सरकार की कोशिश है कि अगले शैक्षणिक सत्र तक प्रदेश के सभी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में आवश्यक शिक्षक उपलब्ध हों। शिक्षकों की उपस्थिति से बच्चों को अब नियमित मार्गदर्शन मिलेगा, शैक्षणिक गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा और समूचे अंचल में शिक्षा के प्रति जागरूकता की नई लहर दौड़ पड़ी है।

इस प्रकार, जशपुर जिले के रैंगारमुंडा और मुण्डाडीह जैसे गांवों में युक्तियुक्तकरण की यह पहल न केवल शिक्षा को बल दे रही है, बल्कि ग्रामीण समाज में सरकार के प्रति विश्वास और सहभागिता का आधार भी मज़बूत कर रही है। यह छत्तीसगढ़ सरकार के संकल्प– "सब पढ़ें, सब बढ़ें" की दिशा में एक सार्थक कदम है।

गर्मी के मौसम में मूंगफली की खेती किसानों के लिए लाभदायक

धान के बदले मूंगफली की फसल से ज्यादा मुनाफा कमा सकते है किसान

जशपुरनगर । जशपुर जिले के किसान अब गर्मी के मौसम में खेती से अतिरिक्त आय अर्जित कर अच्छे जीवन यापन कर रहे हैं।

राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में दूरस्थ अंचल में निवासरत किसानों और जरूरतमंदों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

इसी कड़ी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन) योजना के तहत बगीचा विकासखण्ड के ग्राम दुर्गापारा निवासी गुरुनारायण को धान के बदले ग्रीष्मकालीन मूंगफली फसल की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और योजना के तहत 20 किलोग्राम मूंगफली बीज कृषि विभाग से निःशुल्क प्रदाय किया गया है।

किसान गुरुनारायण ने बताया कि उनके पास कुल 3.303 हेक्टर जमीन हैं जिसमें वे खरीफ सीजन में धान की खेती करते हैं तथा रबी सीजन में भी कुछ रकबे में धान की खेती करते हैं। जिससे खेती का खर्चा ज्यादा एवं उत्पादन अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं मिल पाता था पानी की खपत भी बहुत ज्यादा होती थी।

उन्होंने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री रवि रोशन टोप्पो से सम्पर्क करके अब धान के बदले ग्रीष्मकालीन मूंगफली फसल की खेती कर रहे हैं।

कृषि विभाग से उन्हें निःशुल्क राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन) योजना के तहत 20 किलोग्राम मूंगफली बीज प्राप्त हुआ और उन्होंने 0.200 हे. रकबे में मूंगफली फसल की खेती किए हैं। गुरु नारायण बताया कि उन्हें ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा बीज के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्व खाद एवं दवाई भी दिया गया।

जिससे उनको लागत में कमी आयी

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना बनी रजनीकांत के लिए वरदान

- **प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना बनी रजनीकांत के लिए वरदान**
- **छत्तीसगढ़ में रूफटॉप सोलर सिस्टम से उपभोक्ता हो रहे आत्मनिर्भर, बिजली बिल से मिल रही बड़ी राहत**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना ने प्रदेश के आम नागरिकों को अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाकर खुद बिजली पैदा करने की सुविधा दी है, जिससे न केवल पर्यावरण को फायदा हो रहा है, बल्कि उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से लाभ पहुंच रहा है। घरों में रूफटॉप सोलन सिस्टम लगाए जाने से बिजली बिल शुन्य हो रहा है, इससे उपभोक्ता बिजली के लिए आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। सरकार से मिल रही है सब्सिडी

इसी योजना से लाभान्वित हुए हैं जांजगीर-चांपा जिले के चांपा नगर निवासी श्री रजनीकांत राठौर। उन्होंने अपने मकान की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया है, जिसकी कुल लागत 1.80 लाख रुपए रही। इसमें उन्हें सरकार की ओर से 78 हजार रुपए की सब्सिडी प्राप्त हुई। श्री राठौर ने बताया कि पहले उनका बिजली बिल काफी ज्यादा आता था, लेकिन अब बिल पूरी तरह शून्य हो गया है। उन्होंने इस योजना को आमजन के लिए आर्थिक रूप से राहत देने वाली और पर्यावरण हितैषी बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत राज्य के पात्र उपभोक्ताओं को 78 हजार रूपए तक की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जा रही है। योजनांतर्गत 0 से 105 यूनिट मासिक खपत के लिए 1 से 2 किलोवाट सोलर प्लांट पर 30 हजार से 60 हजार रुपए तक अनुदान, 150 से 300 यूनिट मासिक खपत के लिए 2 से 3 किलोवाट सोलर प्लांट पर 60 हजार से 78 हजार रुपए तक अनुदान, औसत मासिक विद्युत खपत 300 से अधिक यूनिट के लिए 3 किलो वॉट से अधिक रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता हेतु 78 हजार रूपए तक का अनुदान का प्रावधान है।इस योजना ने छत्तीसगढ़ में न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है, बल्कि लाखों घरों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। श्री रजनीकांत की तरह प्रदेश के अनेक परिवार अब अपने बिजली बिल से पूरी तरह मुक्ति पा चुके हैं।

डबरी निर्माण से सवंरी किस्मतः बहुफसली खेती और मछली पालन से बढ़ी आय

रायपुर। डबरी निर्माण से संवरी किस्मतः बहुफसली खेती और मछली पालन से बढ़ी आयजशपुर जिले के फरसाबहार विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत हेटघींचा के किसान श्री धनुर्जय यादव ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत डबरी निर्माण करवा कर अपनी कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा से सुसज्जित कर लिया है। डबरी बनने के बाद न केवल उनके खेतों में हरियाली लौट आई है, बल्कि उन्होंने बहुफसली खेती और मछली पालन शुरू कर अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि भी दर्ज की है।

धनुर्जय यादव ने बताया कि कृषि ही उनके परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है, लेकिन पानी की कमी के चलते वे केवल एक ही फसल पर निर्भर थे। गांव के अन्य किसानों को डबरी योजना से लाभ लेते देख उन्होंने भी डबरी निर्माण का प्रस्ताव

ग्राम पंचायत में दिया। लगभग 2.97 लाख रूपय की लागत से बनी इस डबरी के निर्माण में कुल 1244 मानव दिवस का रोजगार भी सृजित हुआ।

डबरी निर्माण के बाद उन्होंने आलू, प्याज, मिर्च, करेला, भिंडी, बरबट्टी, गोभी जैसे कई प्रकार की सब्जियों की खेती प्रारंभ की है। अब वे न केवल घर की सब्जी की जरूरतें स्वयं पूरी कर रहे हैं, बल्कि अतिरिक्त उत्पादन को बाजार में बेचकर अच्छी आय भी अर्जित कर रहे हैं। साथ ही वे मत्स्य पालन से भी अतिरिक्त लाभ कमा रहे हैं। धनुर्जय यादव कहते हैं, ÷पहले मैं केवल बारिश के भरोसे खेती करता था, लेकिन अब सालभर उत्पादन संभव हो पाया है। डबरी से खेतों को सिंचाई मिलती है और इससे पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है।

डबरी निर्माण से ना सिर्फ खेती की दिशा बदली, बल्कि गांव के अन्य किसान भी इस योजना से प्रेरित होकर आगे आ रहे हैं। धनुर्जय अब अपने अनुभव से अन्य ग्रामीणों को भी मनरेगा जैसी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

डबरी के पानी से किसान के खेतों में आई हरियाली

■ **बहुफ़सली खेती का ले रहे लाभ**

■ **आलू, प्याज, मिर्च, करेला, भिंडी, बरबट्टी, गोभी, सब्जी की खेती से आय में हुई बढ़ोत्तरी**

जशपुरनगर। फ़रसाबहार विकासखण्ड मुख्यालय से 8 किमी. दूरस्थ स्थित ग्राम पंचायत हेटघींचा के धनुर्जय यादव ने कृषि कार्यों में सहयोग एवं सिंचाई के उद्देश्य से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत गाँव में अन्य लोगों द्वारा लिए जा रहे लाभ को देखकर डबरी निर्माण कार्य स्वीकृत कराने की ठानी।

ग्रामीण ईलाका होने के कारण यहां के ग्रामीण मुख्य रूप से कृषि कार्य पर ही निर्भर रहते हैं।

जब हितग्राही को मनरेगा योजना अंतर्गत डबरी निर्माण की जानकारी प्राप्त हुई तो वे इस योजना से डबरी निर्माण कार्य हेतु अपने ग्राम पंचायत में निर्माण एजेंसी सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक से संपर्क कर डबरी निर्माण हेतु प्रस्ताव दिया। जिस पर उन्हे लागत राशि रू. 2.97 लाख कि स्वीकृति प्राप्त हुई।

हितग्राही श्री धनुर्जय ने बताया की कृषि ही उनका मूल पेशा है एवं जीवन यापन के लिये मुख्य रूप से उनका परिवार को कृषि पर ही निर्भर रहना पड़ता है। चूंकि वर्तमान समय में कृषि कार्य हेतु पानी की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण अक्सर फ़सल पर सुखे का प्रभाव पड़ने लगता था। इस समस्या से निपटने के लिए उन्हे डबरी निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई जिसे उन्होंने मनरेगा से प्राप्त किया।

उन्होंने ने बताया कि डबरी निर्माण कार्य में कोई कठिनाई तो नहीं आई किन्तु हितग्राही के मन में कार्य को लेके संशय बना हुआ था। कि कहीं डबरी निर्माण के स्वीकृति पश्चात् उसकी भूमि का रकबा कम न हो जाए डबरी स्वीकृत होने के पश्चात कार्य हेतु श्रमिक मिलेंगे या नहीं बरसात से पूर्वकार्य समाप्त हो पायेगा की नहीं।

डबरी निर्माण कार्य के स्वीकृति की प्रक्रिया–महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत हेटघींचा जनपद पंचायत फ़रसाबहार, जिला-जशपुर ग्राम पंचायत हेटघींचा में और भी विभिन्न प्रकार के हितग्राही मूलक कार्यों का ग्राम सभा में अनुमोदन किया गया जिसमें श्री धनुर्जय यादव की डबरी निर्माण कार्य भी शामिल था।

उक्त डबरी निर्माण कार्य में कुल 1244 मानव दिवस का रोजगार प्रदान किया गया। सर्वप्रथम उक्त कार्य को ग्राम सभा में शामिल किया गया था।

डबरी निर्माण हो जाने से हितग्राही अत्यंत प्रसन्न है। वर्तमान में उनकी आय का स्त्रोत भी बढ़ने लगा हैं। चूंकि पहले उसे कृषि कार्य हेतु बारिश के मौसम पर ही निर्भर रहना पड़ता था, जिससे एक ही फ़सल का ही उत्पादन हो पाता था। वर्तमान में हितग्राही द्वारा बहुफ़सलीय खेती का लाभ लिया जा रहा है। हितग्राही श्री धनुर्जय यादव द्वारा बताया गया कि डबरी का निर्माण हो जाने से वह साग-सब्जी जैसे- आलू, प्याज, मिर्च, करेला, भिंडी, बरबट्टी, गोभी, आदि का समय-समय पर उत्पादन करने लगा है जिससे स्थानीय बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफ़ा ले रहा है। अब घर की सब्जी हेतु भी उसे बाजार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। डबरी निर्माण हो जाने से पानी की समस्या का भी समाधान हो गया है।

धनुर्जय यादव कृषि कार्य हेतु केवल मानसून पर ही आश्रित रहता था। उसके पास आय का काई विशेष स्त्रोत नहीं था। डबरी निर्माण होने से न केवल पानी की समस्या का समाधान हुआ बल्कि उसके आय के स्त्रोत में भी बढ़ोत्तरी हुई।

डबरी निर्माण हो

जाने से उसके कृषि कार्य हेतु पानी का समस्या का समाधान हो गया है। वह इस योजना से संतुष्ट है। हितग्राही द्वारा गांव के अन्य लोगों को भी योजना का लाभ लेने की अपील की जा रही है। वह मत्स्य विभाग से मछली पालन का भी लाभ ले रहा है।

सपनों का घर : पहाड़ी कोरवा महिला फूलोबाई को मिला पक्का आवास

रायपुर। जशपुर जिले के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की महिला श्रीमती फूलोबाई को प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत पक्का मकान मिला है। यह मकान उनके वर्षों पुराने संघर्षों का सुखद अंत और आत्मनिर्भर जीवन की नई शुरुआत है। फूलोबाई जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पंड्रापाठ की निवासी हैं। लंबे समय तक उन्होंने कच्चे घर में कठिनाइयों से भरा जीवन बिताया – बरसात में टपकती छत, जहरीले जीवों का डर और असुरक्षित माहौल उनका रोजमर्रा का हिस्सा था। लेकिन अब, जब उनका पक्का घर बनकर तैयार हो चुका है, तो वह भावुक होकर कहती हैं कि "बरसात में जब छत टपकती थी तो सारी रात जागते कटती थी। अब मैं पहली बार चैन से सो पाती हूँ। यह सिर्फ घर नहीं, मेरे सपनों का महल है। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के माध्यम से पहाड़ी कोरवा जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की ओर अग्रसर किया जा रहा है। फूलोबाई ने इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा, "यह घर मेरे लिए सिर्फ छत नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।

सुरक्षित मातृत्व की ओर छत्तीसगढ़ का सशक्त कदम

■ **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान से महिलाओं को मिल रहा लाभ**

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। विशेषकर दूरस्थ आदिवासी अंचल दंतेवाड़ा में यह अभियान गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने हाल ही में कहा कि माताओं का स्वास्थ्य ही समाज की नींव है। राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक महिला को सुरक्षित मातृत्व और नवजात को स्वस्थ जीवन मिले। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अभियान की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित किया कि राज्य के हर जिले में मातृ स्वास्थ्य सेवाएं गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध सुलभ हों।दंतेवाड़ा जिले में अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रसव पूर्व विशेष जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत के निर्देशन में जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में यह अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय रामटेके ने बताया कि 9 जून 2025 तक जिले में 4,555 गर्भवती महिलाओं का पंजीयन किया गया है। इनमें से 2,000 से अधिक महिलाओं ने जांच शिविरों में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।

जुनवानी से चिखलीटोला तक बनेगी पक्की सड़क

■ **अब सफ़र होगा आसान, मुख्यमंत्री की पहल से खुश हैं ग्रामीण**

रायपुर। बालोद जिले के डौण्डी वनांचल क्षेत्र के ग्राम जुनवानी से चिखलीटोला तक की कच्ची और पथरीली सड़क अब पक्की बनेगी। इस क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए यह सड़क पहले एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कच्चे रास्तों के कारण उन्हें 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 30 किलोमीटर का लंबा सफ़र करना पड़ता था। यह रास्ता पहाड़ी इलाकों से गुजरता था और इसके कारण ग्रामीणों को समय, मेहनत और संसाधनों की भारी बर्बादी होती थी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के दौरान इस सड़क निर्माण के लिए 11 करोड़ 47 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इससे न केवल पक्की सड़क निर्माण होगा, बल्कि इस क्षेत्र में विकास की नई शुरुआत भी होगी। पूर्व जनपद पंचायत सदस्य श्री संजय बैस ने कहा कि इस सड़क के बन जाने से क्षेत्र का विकास तेज़ी आएगी। यह विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण श्री हरिश्चंद्र नायक ने भी बताया कि श्रमदान से बनाए गए इस रास्ते को अब पक्का किए जाने की मांग पूरी होने जा रही है। अब तीन किलोमीटर की दूरी को तय करने में जो समय और पैसा खर्च होता था, वह दोनों बचेंगे। इस पक्की सड़क से ग्रामीणों को बाजार तक आसानी से पहुंच मिलेगी, किसान अपने खेतों तक सरलता से जा सकेंगे, और इस क्षेत्र के लोगों की जीवनशैली में एक बड़ा बदलाव आएगा।

यह सड़क केवल दो गांवों को जोड़ने का काम नहीं करेगी, बल्कि यह क्षेत्र के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार जैसी सुविधाओं तक पहुंच बढ़ेगी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का दिल से आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने उनकी मेहनत और संघर्ष को सम्मानित किया और उनके सपनों को साकार किया। इस पक्की सड़क के निर्माण की स्वीकृति मिलने से क्षेत्र में एक नई उम्मीद और विश्वास का संचार हुआ है।

सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक

मंत्री केदार कश्यप बोले- किसानों को सुगमता से रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराएं

- प्रदेश में इस साल 1175 दुग्ध, 120 मत्स्य तथा 532 पैक्स के गठन का लक्ष्य, खरीफसीजन 2025 के लिए 7800 करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य
- लगभग 5 लाख किसानों को 2241 करोड़ का ऋण वितरित

रायपुर। सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज महानदी मंत्रालय भवन में सहकारिता विभाग की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति, भण्डारण एवं किसानों को वितरण की स्थिति की गहन समीक्षा की। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि, किसानों को सुगमता से रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सहकारी समितियों की है। किसानों की डिमांड को देखते समितियों में नियमित रूप से खाद का भण्डारण एवं वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि किसानों को डीएपी के विकल्प के रूप में अन्य उर्वरकों के उपयोग के लिए जागरूक किया जाना चाहिए।

मंत्री श्री कश्यप ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों को खाद के लिए भटकना न पड़े। निजी क्षेत्र की दुकानों में किसी भी तरीके की गड़बड़ी न हो इस पर भी कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। उन्होंने उर्वरकों को निर्धारित दाम से अधिक मूल्य पर बेचने और कालाबाजारी की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि, किसानों के हितों का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए।

गावों में किसानों तक पहुंचाएं सहकारिता का लाभ : कश्यप

मंत्री श्री कश्यप ने अधिकारियों को राज्य में सहकारिता को मजबूत करने और ग्रामीणों, किसानों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी समितियों के गठन के निर्देश दिए। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि सहकारिता से समृद्धि के लिए यह जरूरी है। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में 11650 ग्राम पंचायतें है, जिनमें 2058 पैक्स, 1958 मत्स्य, 1009 दुग्ध तथा 1055 लघु वनोपज सहकारी समितियां पंजीकृत है। राज्य की 8611 सहकारी समिति विहीन ग्राम पंचायतों का चिन्हांकन कर युक्तियुक्त करते हुए 1279 अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को आच्छादित किया गया है। इस वर्ष 1175 दुग्ध, 120 मत्स्य तथा 532 पैक्स के गठन का लक्ष्य है।

ऋण वितरण की समीक्षा

बैठक में खरीफवर्ष 2025 के लिए ऋण वितरण की भी गहन समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि इस साल 7800 करोड़ रूपए के ऋण वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 4.90 लाख किसानों को 2441 करोड़ रूपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। बैठक में अधिकारियों को 30 जून तक सभी सहकारी समितियों का ऑडिट पूरा कराने के निर्देश दिए है।

ये अफसर रहे मौजूद

बैठक में सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, सचिव श्री सी.आर. प्रसन्ना, एमडी मार्कफेड श्रीमती किरण कौशल, संचालक कृषि श्री राहुल देव, अपेक्स एमडी श्री के.एन. काण्डे, अपर आयुक्त श्री हितेश दोषी सहित सभी संभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सहकारी समितियों के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों का हो रहा वितरण

बैठक में जानकारी दी गई कि, खरीफ सीजन 2025 के लिए सहकारिता के लिए 10.72 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है। इसके विरूद्ध 4.10 लाख मीट्रिक टन का भण्डारण हुआ है, जो कि लक्ष्य का 38.23 प्रतिशत है। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों का वितरण जारी है। 31 मई की स्थिति में 1.57 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण किसानों को किया जा चुका है। सहकारी समितियों में वर्तमान में 2.52 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक उपलब्ध है।

एनसीडीसी उत्कृष्ट पैक्स समितियों को करेगी सम्मानित, 31 अगस्त तक मंगाए गए नामांकन

प्राथमिक स्तर की समितियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाना और उनकी भूमिका को मान्यता देना है पुरष्कृत करने का उद्देश्य

रायपुर। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा **'एनसीडीसी सहकारी उत्कृष्टता व योग्यता क्षेत्रीय पुरस्कार 2025'** के लिए प्रदेश के प्राथमिक सहकारी समितियों से 31 अगस्त 2025 तक नामाकंन मंगाया गया है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) ने देश के सहकारी विकास में सहकारी समितियों द्वारा निभाई गई भूमिका भूमिका को पहचानने के लिए राज्य में प्राथमिक सहकारी समितियों को हर दो साल में सहकारी उत्कृष्टता और योग्यता के लिए पुरस्कार प्रदान करने की योजना शुरू की है।

योजना का उद्देश्य –

समितियों की भूमिका को मिलेगी मान्यता

i) देश के सहकारी विकास के लिए सहकारी समितियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना। ii) जमीनी स्तर की सहकारी समितियों यानी प्राथमिक स्तर की समितियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना और सामाजिक-आर्थिक विकास में उनकी भूमिका को मान्यता देना। iii) सहकारी समितियों के संवर्धन और विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था के रूप में एनसोडीसी की भूमिका का प्रचार-प्रसार करना है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives. Always!
सहकारिताओं की सहायता में सदैव तत्पर!

नई पहल करने वाली समितियां पुरष्कार का भागीदार बनेंगी

चूंकि 2025 को "अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, इसलिए वर्ष 2025 में NCDC क्षेत्रीय पुरस्कार सहकारी क्षेत्र को प्रेरित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय की नई पहलों को अपनाने वाली सहकारी समितियों तथा अच्छे काम करने वाले सहकारी एफ्मीओ को भी मान्यता देंगे और पुरस्कृत करेंगे। कार्यक्रम राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता एक प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति करेंगे।

इन वर्गों में मिलेंगे पुरष्कार

एनसीडीसी क्षेत्रीय पुरस्कार सहकारी एफ्मीओ सहित दस (10) प्राथमिक सहकारी समितियों को दिया जाएगा। पुरस्कार में पाँच (5) प्रथम पुरस्कार सहकारी उत्कृष्टता पुरस्कार शामिल हैं जिसमें 35,000 रुपये का नकद पुरस्कार और मान्यता/प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और पाँच (5) द्वितीय पुरस्कार सहकारी योग्यता पुरस्कार - जिसमें 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार और मान्यता/ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। क्षेत्रीय पुरस्कार योजना, दिशानिर्देश (अनुबंध-I), पात्र समितियों द्वारा भरा जाने वाला आवेदन पत्र (अनुबंध-II), चयन मानदंड (अनुबंध-III) और श्रेणी 3 के तहत समिति का चयन करने के लिए चयन समिति द्वारा मूल्यांकन के लिए एमओसी पहलों की सूची (अनुबंध-IV) तैयार किया गया है।

चार सदस्यीय समिति करेगी विजेताओं का चयन

सहकारी समितियों का चयन सचिव (सहकारिता) या आयुक्त (सहकारिता) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर गठित चार सदस्यों वाली समिति द्वारा किया जाएगा और क्षेत्रीय निदेशक, NCDC, रायपुर इसके सदस्य संयोजक होंगे। इस संबंध में NCDC द्वारा विस्तृत योजना दिशानिर्देश, भाग लेने वाली समितियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप, समितियों के चयन में अपनाए जाने वाले मानदंड के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई हैं।

स्वामी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा प्रकाशक एवं मुद्रक छग राज्य सहकारी संघ रायपुर द्वारा मयंक ऑफसेट रायपुर से मुद्रित कराकर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित 16, पार्क स्ट्रीट-3, चौबे कालोनी रायपुर से प्रकाशित।
संपादक मंडल- विवेकानंद झा (प्रधान संपादक), विवेक पांडे (संपादक), फोन- 0771-4061702, 4031702, 4035702. वेबसाईट www.cgcoop.in E-mail: cgcoopnews@gmail.com